

प्रेषक,

अनूप यधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 5 जनवरी, 2010

विषय: कुम्भ मेला, 2010 की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत Temporary water supply arrangement for Kumbh Mela, 2010 for Dheerwalli parking कार्य हेतु प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3379/कु.मे./पे.ज.नि., हरिद्वार दिनांक 12.12.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रु. 51 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रु. 46.28 लाख (रु. छियालीस लाख अठाइस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए वित्तीय वर्ष 2009-10 में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत धनराशि व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. टिबरी पार्किंग या अन्य स्थलों हेतु अस्थायी पेयजल योजना में बची धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा करा दिया जाएगा एवं यदि प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष कार्य का कोई अंश अन्य स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत कर दिया गया हो अथवा स्वीकृत हो तो उतनी धनराशि कम आहरित की जाएगी।
2. अस्थायी कार्य के अन्तर्गत मेला उपरान्त पाईप आदि अन्यत्र उपयोग होने वाली सामग्री के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाए एवं रिफण्ड होने वाले भाग के सापेक्ष धनराशि रिफण्ड कर दी जाएगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का यथाआवश्यकता दो बराबर किश्तों में आहरण किया जाएगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही अगली किश्त का कोषागार से आहरण किया जाएगा। उक्त धनराशि कोषागार से आहरित करके निकाय द्वारा अपने पी.एल.ए. खाते में रखी जाएगी और इसका उक्त खाते से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाएगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए। कार्य पूर्ण होने के बाद इसके गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 'थर्ड पार्टी चैकिंग' की व्यवस्था भी की जाएगी और उक्त तृतीय पक्ष से चैकिंग की रिपोर्ट शासन को भी समय-2 पर दी जाएगी। उक्त पर होने वाला व्यय उक्त अनुमोदित लागत से ही वहन किया जाएगा।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
6. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण कराया जाएगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी दशा में अनुमन्य न होगा। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितनी राशि स्वीकृत की गई है।
7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्माण कार्य तथा इस हेतु निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु मानकों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाए। किसी विशेष नियम का अनुपालन न होने पर समस्त दायित्व विभाग का ही माना जाएगा।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपर्युक्त सामग्री का ही प्रयोग में लाया जाए।
11. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाए।

क्रमशः

12. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/ भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
14. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि इस पर अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके, उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जाएगा।
15. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाए।
16. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
17. कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी एवं संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्णतया उत्तरदायी माने जाएंगे।
18. अकुशल व कुशल श्रमिकों तथा अन्य नियोजित दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों को शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य मजदूरी ही भुगतान की जाएगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009-39(सा.)/2006 -टी.सी. दिनांक 24नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रु. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तदस्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 844/XXVII(2)/200 दिनांक 01जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

नवदीय,

(अनूप पद्मावन)
सचिव।

संख्या : 1709 (1)/IV(1)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पी.डी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनुसचिव।